

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



फोन:- 230200, 230400 फैक्स:- 07469-230600

वर्ष: 17

संख्या: 274

प्रभात

हिण्डौन सिटी, गुरूवार 7 अगस्त, 2025

पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कराने के लिए स्पीकर के ओएसडी सुप्रीम कोर्ट जायेंगे?

दूसरी ओर, एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दर्ज कराने वाले प्रार्थी शेखर मेवाड़ा व कैलाश राम ने सुप्रीम कोर्ट में “केविएट” फाइल की, 5 अगस्त को इस मामले में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6, अगस्ता। एक अहम घटनाक्रम में, अब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट और न्यायाधीश समीर जैन ने 4 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था।

इससे भी ज्यादा चौंकाते और स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा को ओम बिड़ला ने दिल्ली बुलाया था, जहां उन्होंने बिड़ला और राजीव दत्ता, दोनों से मुलाकात की।

संभवतः यह पहला अवसर है, जब किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उस आरोपी से मुलाकात की है, जिसके

- जैसा कि विदित ही है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने, लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ ‘ह्यूमन ट्रेफिकिंग’ के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश चार अगस्त को पारित किये थे।
- अजीबोगरीब बात यह भी है कि कांग्रेस ने भी किन्हीं कारणों से इस प्रकरण में चुप्पी साधने का निर्णय सा ले लिया है। क्योंकि, जब किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने इस मामले की खबर, पीसीसी की वैबसाइट पर डाली तो तुरन्त आदेश आ गया, पार्टी के उच्चतम स्तर से, कि प्रकरण की स्टोरी वैबसाइट पर नहीं दिखाई जाए।

खिलाफ राज्य के हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया हो। हालांकि मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, यह केवल कयास ही है, लेकिन पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों में इस बात को लेकर

खासी चर्चा और उत्सुकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने डीजीपी को क्या निर्देश दिए होंगे। सूत्रों के अनुसार, कथित रूप से मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे राजीव दत्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि

हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश को रद्द कराया जा सके। इसके लिए वे एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं, शेखर मेवाड़ा और कैलाश राम ने, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तथा गड़बड़ी की आशंका के कारण पहले ही, 5 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न हो सके।

राजस्थान और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में दत्ता के इस मामले को लेकर काफी चर्चा और दिलचस्पी देखी-सुनी जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कांग्रेस नेता ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 06 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत यहां बने केन्द्रीय सचिवालय भवनों में से एक कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उनके साथ केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी थे। इस दौरान मोदी ने कर्तव्य भवन का दौरा किया और यहां बनायी गयी सभी सुविधाओं का निरीक्षण

- 50 हजार वर्ग मीटर में फैला यह भवन पूर्णतया ईकोफ्रेंडली है, और कई प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय इसी भवन में बनाए जाएंगे।

भी किया।

यह लगभग एक लाख 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें दो बेसमेंट और सात तल (भूतल 6 तल) हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी

जयपुर, 6 अगस्ता। राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में प्रति-जवाब पेश करने के लिए याचिकाकर्ता को 8 अगस्त का समय दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपिठ ने ये आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर

- याचिकाकर्ता 8 अगस्त को प्रति जवाब पेश करेंगे।

सुनवाई करते हुए दिए।

ईडी की ओर से याचिकाकर्ता की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका को बताया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि की लौटाना भी बताया जा रहा है, तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्तत प्राप्त की है। इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत आरोपी को उस समय ही जमानत दी जा सकती है, जब अदालत इस बात से प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने भारत पर रूस से “ऑयल” खरीदने के एवज़ में 25 प्रतिशत टैरिफ और लगाया

अमेरिका ने ऐसी पैनल्टी चीन पर लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई, हालांकि, चीन भी भारी मात्रा में रूस से “ऑयल” खरीदता है

- इस बड़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय माल अमेरिका के बाजारों से लुप्त हो जाएगा तथा भारत को अन्य मार्केट ढूंढ़ने पड़ेंगे, अपना माल बेचने के लिए।
- पर, रूस के अलावा अन्य स्रोतों से ऑयल खरीदने का विकल्प नहीं बचा है भारत के समक्ष। क्योंकि, अन्य स्रोतों से ऑयल की खरीद बहुत महँगी पड़ेगी भारत को।
- भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत कम है तथा निर्यात बंद होने से इतना नुकसान नहीं होगा, जितना “ओपन मार्केट” से ऑयल खरीदने से होगा।
- चीन पर पैनल्टी नहीं लगाने से ट्रंप की “टी.ए.सी.ओ.” (ट्रंप आलवेज़ चिकन्स आउट) की छवि को और स्पष्ट और मजबूत कर देता है।

बढ़ जाएंगी।

ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब अमेरिका की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत चल रही है। ट्रंप रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वे जल्दी से यूक्रेन में अपना युद्ध समाप्त करें।

चाहे अनचाहे, इस कदम ने भारत

को अमेरिका और रूस जैसी प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के बीच चल रही भू-राजनीतिक खींचतान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतिक दांव-पेंच खेल रहे हैं। भारत ने ट्रंप की भारतीय निर्यात पर सेकन्डरी प्रतिबंध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उत्तरकाशी आपदा में 100 से अधिक के मरने की आशंका

आधी रात के बाद बादल फटने से आई बाढ़ से भारी विनाश हुआ कई गांव शेष दुनिया से कट गए हैं

- गंगोत्री नेशनल हाईवे को भारी नुकसान हुआ है। धराली से 40 किलोमीटर दूर भटवाड़ी के पास ही बैरिकेड लगाकर हाईवे को बंद कर दिया गया है।
- राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए विमानों से राहत सामग्री गिराई, क्योंकि खराब मौसम और भारी विनाश के कारण राहत व बचाव दल आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

हिस्से धंस चुके हैं या टूट चुके हैं, जबकि कई अन्य हिस्से भूस्खलन के कारण बह गए हैं। फिलहाल यह हाईवे धराली से लगभग 40 किलोमीटर पहले भटवाड़ी के पास बैरिकेड लगा दिए गए हैं।

क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इनकी बहाली के प्रयास जारी हैं, लेकिन भारी तबाही और लगातार खराब मौसम के चलते प्रगति धीमी है। गंगनानी के पास

एक पुल पूरी तरह से बह गया है, जिससे प्रभावित इलाका और अधिक अलग-थलग पड़ गया है

राज्य सरकार ने हवाई राहत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हेलीकॉप्टरों से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए और प्रभावित लोगों के लिये आवश्यक सामग्री गिरायी जा रही है। मलबे से एक और शव मिलने के बाद, अब तक आधिकारिक तौर पर केवल पाँच मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और निवासियों को आशंका है

कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। जमीन पर काम कर रही राहत टीमें मलबे में फंसे लोगों को तलाश कर रही हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, नुकसान का जायज़ा लिया और पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हर एक जीवन कीमती है और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी हालात का जायज़ा लिया और मुख्यमंत्री धामी से सीधे बात कर संकटपूर्ण स्थिति को जानकारी और सरकारी प्रयासों और उपायों के बारे में अपडेट लिया।

धराली तक वैकल्पिक मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं, लेकिन सड़क (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक अक्टूबर से बहाल होंगी एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

नई दिल्ली, 06 अगस्ता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया के विमानों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, हालांकि अब

- अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सुरक्षा जांच लंबित होने की वजह से एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सेवा पर आंशिक रोक लगा दी गई थी।

धीरे-धीरे एयर इंडिया के विमानों की आवाजाही सामान्य होती जा रही है। इस बीच बुधवार को एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कैप्टेन विल्सन ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकी गई

नैनीताल, 06 अगस्ता। उत्तराखंड के कुमाऊं में बादल फटने का कहर फिलहाल बुधवार शाम को थम गया, लेकिन उसका असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बुधवार को धारचूला से आगे नहीं बढ़ पाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश मानसरोवर यात्रा का 48 सदस्यीय चौथा दल मंगलवार को

- उत्तराखंड में आई आपदा की वजह से यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंच गया था। रात्रि विश्राम के बाद, आज दल को उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित पहले आधार शिविर गुंजी पहुंचना था, लेकिन अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन होने से धारचूला-लिपुलेख मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया।

एस.सी.ओ. सम्मेलन में प्र.मंत्री मोदी जायेंगे इस माह

भारत की कूटनीति के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि भारत ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता, कि दोनों “सुपर पावर” ग्रुप में से एक-एक का चयन करना पड़े उसे

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने के अंत में चीन जा रहे हैं, जहाँ वे शंघाई कोऑपेरेशन आर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और भारत प्रमुख शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के बीच फंसा हुआ है। इस यात्रा की पृष्ठभूमि विशेष रूप से जटिल है, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव भी बना रहे हैं, जबकि रूस, भारत का लंबे समय से रणनीतिक

साझेदार रहा है। इन घटनाओं ने भारत की कूटनीतिक गुंजाइश को सीमित कर दिया है, जिससे नई दिल्ली के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में विविधता लाना आवश्यक हो गया है।

इस पृष्ठभूमि में, मोदी की चीन पहल को एक रणनीतिक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा कूटनीतिक दांव, जो अमेरिकी दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है। भारत भले ही वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध हो, विशेषकर प्रौद्योगिकी, रक्षा और ईंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में, लेकिन बीजिंग के साथ नए सिरे से संवाद एवं अधिक संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है, जो रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत

- भारत, अमेरिका के साथ टैक्नॉलजी, डिफेंस सहयोग तो चाहता है, पर, क्षेत्रीय मामलों में अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता की इच्छा भी रखता है।

- साथ ही पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किये गये नरसंहार वाकिया भी ताज़ा है, भारत के दिलो-दिमाग पर। अतः, चीन द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना हर मामले में, चाहे वह मामला आतंकवादी गतिविधियों के बारे में ही क्यों न हो, भारत के लिए पीड़ादायक अहसास है।

- एस.सी.ओ. सम्मेलन में वॉशिंगटन, मॉस्को व बीजिंग के बीच कैसे संतुलन बैठाकर आगे बढ़ा जाए, यह भारत के लिए वाकई में चुनौती है।

- चर्चा है कि सम्मेलन के दौरान प्र.मंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन व चीन के प्रेंसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं।

प्रतिद्वंद्वी वैश्विक शक्तियों के बीच किसी एक पक्ष का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

हालांकि, यह संवाद कई

जटिलताओं से भरा हुआ है। यह यात्रा उस समय हो रही है, जब कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में कई भारतीय सुरक्षा कर्मियों और

नागरिकों की जान चली गई। इस घटना ने पाकिस्तान के प्रति चीन के रुख को लेकर भारत की चिंताओं को फिर से उभार दिया है, विशेष रूप से इस बात

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बढकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

शहरों की बिगड़ती आबोहवा, नागरिकों का स्वास्थ्य ख़तरे में

राजस्थान एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। वायु, जल, ध्वनि और औद्योगिक प्रदूषण के साथ-साथ खनन से उत्पन्न धूल ने न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डाला है। शहरों की बिगड़ती आबोहवा ने सांस लेने में तकलीफ, बीमारियों में वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन का गम्भीर संकट खड़ा कर दिया है। आज यह संकट केवल बड़े शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के शहरों में वायु, जल, ध्वनि, औद्योगिक और खनन से संबंधित प्रदूषणों के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज वायु प्रदूषण राजस्थान के शहरों में एक गंभीर समस्या बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, श्रीगंगानगर, जयपुर, दौसा, कोटा और भिवाड़ी जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अप्रैल 2०25 में श्रीगंगानगर में एक्यूआई 321 तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों से कई गुना अधिक है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियाँ और खनन से उत्पन्न धूल शामिल हैं। जयपुर, जो पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है, में यातायात का दबाव और सड़कों पर उड़ने वाली धूल के कारण पीएम 1० और पीएम 2.5 जैसे महीन कणों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कण फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रॉन्काइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) को बढ़ावा दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से भिवाड़ी, अलवर और कोटा में, कारखानों से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक अध्ययन के अनुसार, राजस्थान के शहरों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैसीय प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे एक बहु-प्रदूषक संकट उभर रहा है। भिवाड़ी, जो एक औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है, में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत गैर-प्राप्ति वाले शहरों में शामिल है। राजस्थान के छोटे शहरों और कस्बों में भी वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, जो पहले केवल बड़े शहरों तक सीमित थी। निर्माण गतिविधियाँ, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी ढांचे के विकास ने भी धूल प्रदूषण के स्तर को की गुना बढ़ा दिया है। विशेष रूप से शुष्क जलवायु और तेज हवाओं के कारण धूल के कण हवा में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब होती है।

वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह पर्यावरणीय संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसके अलावा, वायु प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग पर भी असर डाला है। उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें, जो कभी अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, अब प्रदूषण के कारण अपनी चमक खोती जा रही हैं। राजस्थान सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण इसे किसी न किसी रूप से विफल माना ही जाएगा। राज्य में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर, विशेष रूप से हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर जैसे जिलों में, जहां 3०0 से ऊपर पहुंच गया है, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं, और पराली जलाना प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (‘सॅड’) के तहत कदम उठाए हैं, जैसे पराली जलाने पर रोक और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सीमित रहा है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी में कमी, औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती का अभाव, और पुराने वाहनों पर नियंत्रण की कमी ने समस्या को और गंभीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान सहित अन्य राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर जवाब मांगा है। यह सरकार की निष्क्रियता को तो दर्शाता ही है जनजागरूकता और स्थानीय निकायों के सहयोग की कमी भी एक बड़ी बाधा है। हालांकि, हाल के प्रयासों में राजस्थान पुलिस को पराली जलाने पर निगरानी के लिए तैनात किया गया है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए और सख्त नीतियों, नियमित निगरानी, और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है।

इसी जल प्रदूषण राजस्थान में एक और गंभीर चुनौती है। राज्य में जल संसाधनों की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है, और उस पर जल प्रदूषण ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सोबेज और कृषि अपवाह ने नदियों, झीलों और भूजल को दूषित कर दिया है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक कचरे के कारण कई गांवों में पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। एक टवीट में जोधपुर के अराबा, डोली और धवा जैसे गांवों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक कचरे के प्रभाव का जिक्र किया गया, जहां पानी इतना दूषित हो चुका है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। राज्य की प्रमुख नदियों, जैसे चंबल और बना, में औद्योगिक और घरेलू कचरे का अंधाधुंध निपटान हो रहा है। कोटा और बूंदी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जिसमें भारी धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम और आर्सेनिक शामिल हैं, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ये धातुएं जलीय जीवन को नष्ट करने के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही हैं।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लगेगी।

पाई गई है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण भूजल में धूल और रासायनिक अवशेषों का मिश्रण हो रहा है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में अनुपचारित सोबेज का रिसाव भूजल को और दूषित कर रहा है। यह स्थिति न केवल पीने के पानी की कमी को बढ़ा रही है, बल्कि जलजनित बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा और टाइफाइड के मामलों में भी वृद्धि कर रही है। उदयपुर की फतेहसागर और रंगमण्डा झीलें, जो कभी शहर की शान थीं, अब सोबेज और औद्योगिक कचरे के कारण दूषित हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों में तो राजस्थान के शहरों में खतरा और भी तेजी से उभरा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में वाहनों, कारखानों, लाउडस्पीकरों और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न शोर ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से त्योहारों और सामाजिक आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकरों और पटाखों का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को और बढ़ाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मशीनों और विस्फोटों की आवाज ने शांत वातावरण को नष्ट कर दिया है। खनन गतिविधियां राजस्थान में प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं। राज्य में मार्बल, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और अन्य खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन होता है, जिससे धूल और मसबब का उत्सर्जन होता है। उदयपुर, मकाना और राजमर्ग जैसे क्षेत्रों में खनन से उत्पन्न धूल ने हवा और पानी दोनों को दूषित किया है। यह धूल न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाती है, बल्कि फसलों और मिट्टी की उर्वरता को भी प्रभावित करती है। खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं, जो सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इसके अलावा, खनन से उत्पन्न मलबा नदियों और जलाशयों में बह जाता है, जिससे जल प्रदूषण और बाढ़ का खतरा बढ़ता है।

औद्योगिक प्रदूषण भी राजस्थान के पर्यावरण को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भिवाड़ी, अलवर, कोटा और जोधपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक कचरा न केवल हवा और पानी को दूषित कर रहा है, बल्कि मिट्टी को भी प्रभावित कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण में टेक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाला रंगीन अपशिष्ट जल नदियों और भूजल में मिल रहा है, जिससे आसपास के गांवों में पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। कचरे का प्रबंधन तो एक बड़ी चुनौती है ही। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का ढेर और उसका अנוचित निपटान पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। जयपुर और कोटा जैसे शहरों में कचरे के ढेर खुले में जलाए जाते हैं, जिससे धूल में जहरीले एंजाइमों का उत्सर्जन होता है। प्रदूषण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा और पानी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है, जिससे चिकित्सा खर्च बढ़ा है। सिलिकोसिस, कैंसर, खदब रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, प्रदूषण ने पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित किया है।

हालांकि प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राजस्थान के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्वच्छ ईंधन, जैसे सीएनजी और एलपीजी, को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। लेकिन इन नियमों का अनुपालन और कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए, सरकार ने नदियों और जलाशयों की सफाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। चंबल नदी की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन औद्योगिक अपशिष्ट और सोबेज के निरंतर निर्वहन ने इन प्रयासों को प्रभावित किया है। भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग और बाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को स्थापना पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कुछ शहरों में लाउडस्पीकरों और वाहनों के हॉर्न पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कम ही देखा जाता है। खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन भ्रष्टाचार और स्वच्छताही के कारण यह समस्या बनी हुई है। कचरे के प्रबंधन के लिए, कुछ शहरों में रोसाइक्लिंग और कम्पोस्टिंग सुविधाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये प्रयास अभी प्रारंभिक चरण में हैं।

प्रदूषण की इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, उद्योगों, स्थानीय समुदायों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, औद्योगिक अपशिष्ट के लिए सख्त नियम लागू करना, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर, समुदाय आधारित निगरानी और स्वच्छता अभियान भी प्रभावी हो सकते हैं। राजस्थान की बिगड़ती आबोहवा एक चेतावनी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहरा सकता है। यह न केवल पर्यावरणीय, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आपदा का रूप ले सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि राजस्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को बरकरार रख सके। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। सामूहिक प्रयासों से ही इस संकट से निपटा जा सकता है, और राजस्थान को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र मोहन शर्मा वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक

“वोकल फॉर लोकल” के आह्वान को राज्य सरकार ने आत्मसात किया

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) विशेष.....



हेमन्त सिंह

देश के इतिहास के पन्नों में 7 अगस्त, 19०5 को स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक नया अध्याय जुड़ा था, इस दिन कोलकाता के टाउन हाल से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का शंखनाद हुआ था। स्वदेशी को स्वाभिमान से जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष

2०15 में इसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैण्डलूम डे) के रूप में मनाने की पहल की।

स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हथकरघा को एक नई चेतना दी। वैसे ही स्वत्व एवं गर्व की छवि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के विजन में भी झलकती है और यह मंत्र अब भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का परिचायक भी बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के इस ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान को आत्मसात किया और अपनी ठोस नीतियों के माध्यम से इसे राजस्थान में नई बनावट दी।

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोटा डोरिया की महीनता से लेकर सांगानेर और अजरक प्रिंट तक की परम्परागत कला ने न केवल समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का तराना रचा है बल्कि वस्त्र उद्योग के रुप में आज भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुन रही

- ‘स्वदेशी’ से ‘आत्मनिर्भरता’ तक कालजयी है हमारी विरासत राजस्थान में ‘वोकल फॉर लोकल’ की नई बुनावट है पंच गौरव कार्यक्रम

है। कोटा डोरिया और सांगानेर प्रिंट ने देश की सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्री में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के नये केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ‘राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2०25’ लागू की है।

इसके अंतर्गत हैण्डलूम जैसे ट्रेडिशन को भी को नवीनतम तकनीक से जोड़ने के लिए पर्याप्त और आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, राज्य सरकार ने कोटा, बालोतरा, भीलवाड़ा, पाली के वस्त्र कला के उत्पादों को पंच गौरव जैसे कार्यक्रम का भी हिस्सा बनाया है।

पंच गौरव कार्यक्रम से **पनपती स्थानीय पहचान** :– देश

का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते राजस्थान के सभी अंचलों में अलग-अलग परिस्थितिकी, भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं विशिष्ट संस्कृति देखने को मिलती है। राज्य सरकार पंच गौरव कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक जिले में विशिष्ट एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल को प्रोत्साहित कर रही है।

जैसलमेर की खूबसूरत पीलू जाल (वानस्पतिक प्रजाति), प्रतापगढ़ के थेवा आभूषण (उत्पाद) की बेजोड़ कलाकृति, अनोखी महक से सराबोर बीकानेर की मेथी (उपज), सदियों पुरानी धरोहर की छवि को उकेरता नागीर का मीरा स्मारक (पर्यटन स्थल), सिरोही की उकूछ प्रतिभाओं के सामर्थ्य को दर्शाती तीतरांजी

(खेल) इसके उदाहरण है। स्थानीयता एवं विशिष्टता के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन, पहचान एवं विकास की पंचधारा से प्रदेश के सभी अंचलों के स्थानीय तत्व अब देश-विदेश में ‘ब्रांड राजस्थान’ बन रहे हैं।

आज 7 अगस्त का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता हमारे देश के लिए आत्मगौरव का विषय है। वैश्विक परिदृश्य में जब आज अन्य देश टैरिफ नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारी कालजयी विरासत को संजोते हुए स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को विकल्प की बजाए आवश्यक रूप में अपनाने का मंत्र और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की नीतियाँ इसी दिशा में विकास और विरासत की संतुलित करते हुए एक नए एवं समृद्ध राजस्थान की बुनियाद रख रही हैं।

—हेमन्त सिंह (सहा. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी), मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ

भारत की पेट्रोलियम कंपनियों का महाविलय: यही समय है! सही समय है!

का एकीकरण हुआ, व्यापारियों से

विरोध भी झेलना पड़ा, अफसरों से कड़ा सवाल भी, लेकिन जो एक देश, एक टैक्स, आज हरेक व्यापारी और उपभोक्ता सराह रहा है, वही फायदा पेट्रोलियम में भी मिलेगा।

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां–

भारत को सीखना होगा

दुनिया में सऊदी अरामको जैसी कंपनियां (59० अरब राजस्व, 1.8 ट्रिलियन मार्केट कैप), सिनोपेक–चाइना पेट्रोलियम (487 अरब), पेट्रोचाइना, एक्सॉनमोबिल, शेल जैसे ब्रांड, अपनी भव्य एकीकृत व्यवस्थाओं के बल पर वैश्विक रैंकिंग में टॉप पर हैं। जब हमारी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साथ होगा, तब भारत भी दुनिया की सूची में कहीं आए बड़ जाएगा।

दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों का राजस्व और मार्केट कैप:–

सऊदी अरामको (Saudi Aramco)
वार्थिक राजस्व: लगभग 590 अरब

अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैपिटलाइजेशन: 1.8 ट्रिलियन

अमेरिकी डॉलर

सिनोपेक (China Petroleum & Chemical)

वार्थिक राजस्व: लगभग 487 अरब

अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 58 अरब अमेरिकी डॉलर

पेट्रोचाइना (PetroChina)

वार्थिक राजस्व: लगभग 486 अरब

अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 79 अरब अमेरिकी डॉलर

एक्सॉन मोबिल (ExxonMobil)

वार्थिक राजस्व: लगभग 387 अरब

अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 445 अरब अमेरिकी

डॉलर

शेल पीएलसी (Shell PLC)

वार्थिक राजस्व: लगभग 365 अरब

अमेरिकी डॉलर

मार्केट कैप: 202 अरब अमेरिकी

डॉलर

भारत की मेगा कंपनी की संभावना
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास 13,772 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण 2,०9,०65 करोड़ रुपये है और इसके पास कुल रिजर्व्स 1,72,716 करोड़ रुपये हैं। आज की तारीख में इसका शेयर भाव 148 है। कंपनी की सालाना बिक्री 7,58,1०6 करोड़ रुपये तक पहुंचती है



व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेंगी। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

और शुद्ध लाभ 13,789 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

भारत पेट्रोलियम के पास 4,273 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी है, कंपनी का मार्केट कैप 1,45,665 करोड़ रुपये और रिजर्व्स 77,112 करोड़ रुपये हैं। इसके एक शेयर का दाम अब 336 है। बीपीसीएम ने 4,40,272 करोड़ रुपये की बिक्री की और 13,337 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास 2,128 करोड़ रुपये की इक्विटी, 9०,475 करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण और 49,०16 करोड़ रिजर्व्स हैं। इस समय बाजार में इसका शेयर 425 है। बिक्री 4,34,1०6 करोड़ रुपये की रही जबकि शुद्ध लाभ 6,736 करोड़ रुपये रहा।

तीनों कंपनियों को जोड़ें तो कुल इक्विटी पूंजी 20,173 करोड़ रुपये, कुल मार्केट कैप 4,45,205 करोड़ रुपये और कुल रिजर्व्स 2,98,844 करोड़ रुपये हो जाते हैं। इनकी कुल बिक्री 16,32,484 करोड़ रुपये हैं और मिलानुला शुद्ध लाभ 33,862 करोड़ रुपये तक पहुंचता है।

यदि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सभी बड़ी भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां मर्ज होकर एक “मेगा इंडिया पेट्रोलियम” कंपनी का रूप लेती हैं, तो उसके संभावित फायदे और वैश्विक प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे:–

भारत की ‘मेगा कंपनी’ का संयुक्त वार्थिक राजस्व लगभग 200–25० अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे वह दुनिया की टॉप–5 तेल कंपनियों की कतार में आ सकती है। बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) भी बढ़कर लगभग 200–3०0 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुंच सकती है, जिससे भारत वैश्विक मंच पर दिखेगा।

जनात को पूरे देश में एक ही दर और एक ही क्वालिटी का पेट्रोल–डीजल मिलेगा, जिससे उपभोक्ता प्रीतिायं और भ्रष्टाचार दूर होगा।

आज हर राज्य की अपना टैक्स की दरें अलग–अलग होने से उनके बॉर्डर एरिया में जो पेट्रोल पम्प हैं यदि सस्ता है तो बेशुमार बिक्री होती है और अगर बॉर्डर का दूसरा पम्प महंगा है तो उसकी बिक्री नागण्य होती है और इसका उदाहरण राजस्थान –हरियाणा के बॉर्डर पर जा सकता है।

लॉजिस्टिक्स, बफर स्टॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज आदि पर दोहराव खत्म होगा और अनुमानतः 15–2०

अनावश्यक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनें लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

चर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकतें हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्या सुगमता से बनें लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

चर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकतें हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्रोत से भन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्रोत से भन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।

तक कंपनी की प्रॉफिटबिलिटी बढ़ सकती है। सभी का इन्वेस्टी प्रबंधन खर्च मर्जर के बाद आधा हो जाएगा।

एकीकृत कंपनी देश के लिए निवेश, रोजगार, टेक्नोलॉजी और पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर में तेजी ला सकती है।

ग्लोबल स्टेज पर भारत की ब्रांडिंग मजबूत होगी और “वन ब्रांड, वन कंपनी, वन नेशन” का सपना साकार होगा।

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। भविष्य की जेनरेशन को एक अनुकूल पर्यावरण।

नई कंपनी के बनने से सैकड़ों नई नौकरियाँ, टेक्निकल, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन में शानदार मौके।

इस तरह, भारत की एक विशाल पेट्रोलियम कंपनी विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बूटने, देश की अर्थव्यवस्था को बूट देने और उपभोक्ता जीवन आसान बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

देश के लिए, आम जनता के लिए
अब यह सिर्फ सरकार के सपने की बात नहीं–यह आम आदमी, टैक्सपेयर, व्यवसायी, किसान, व्यापारी, हर नागरिक के विकास का सपना है। भारत के हर कोने में एक ही दर, एक गुणवत्ता का पेट्रोल–डीजल, पारदर्शी सोंदे, स्मार्ट व तेज वितरण। पाइपलाइन से गांव हो या मेट्रो सिटी, गैस–पेट्रोल के बेहतर इस्तेमाल को क्रांति।

अब बदलाव की जरूरत

क्या नई चुनौतियाँ नहीं होंगी? जरूर होंगी। बड़े बदलाव कभी भी बिना विरोध या टकराव के नहीं आते, लेकिन अगर लक्ष्य पारदर्शिता, दक्षता, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी और उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा देना है, तो यह फैसला ऐतिहासिक होगा।

“एक कंपनी, एक ब्रांड, एक क्वालिटी, एक राष्ट्र”–अब समय है भारत को एशिया ही नहीं दुनिया की शीर्ष तेल कंपनियों के साथ बराबरी पर खड़ा देखें। सरकार, विशेषज्ञ, और समाज–सबको आगे आकर इस परिवर्तन की ओर गंभीरता से कदम बढ़ाना होगा।

यदि आपको उल्टा कोई हिस्सा और विस्तर से चाहिए, हर नागरिक की संचारी, भावनात्मक या तथ्यपरक भाषा में चाहिए–तो आप निर्देश दें।

धन्यवाद,

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

जयपुर, राजस्थान

	मेघ नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनें लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।		सिंह व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनें लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।		धनु चर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।
	वृष चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।		कन्या चर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित संपर्क बनेंगे।		मकर चर-गृहस्थी के खुद में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। आज मन में अंतोषाग बना रहेगा।
	मिथुन परिवार में आपसी सहयोग-सम्बन्ध बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		तुला व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।		कुंभ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ बनी रहेगी। आज सम्पन्न रचनात्मकता में व्यतीत होगा।
	पेशाभि व्यक्तिगत परेशानियाँ दूर होने लगेगी। अनेहोनी की आशंका से बचना हुआ मन का थप दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।		वृश्चिक आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।		मीन व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता सुगमता से बनें लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

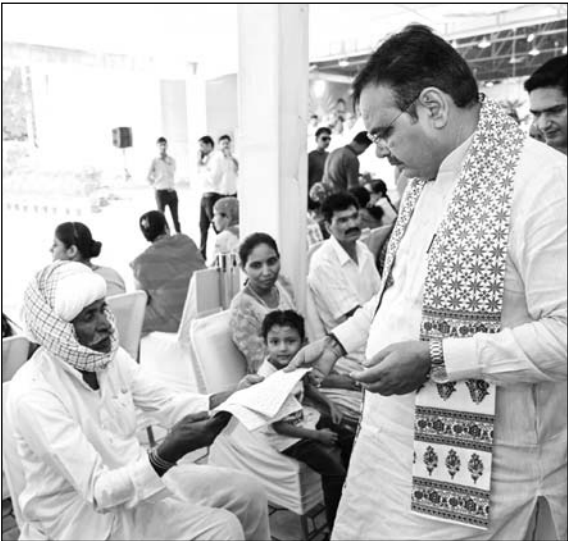
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से जनसुनवाई बनी सुशासन की नई मिसाल

मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। शासन की सेवा का माध्यम मानते हुए यह सरकार

- जयराम और कैलाश को मिला कृषि विद्युत कनेक्शन**
- मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद, अब नहीं सूख रही फसलें**

प्रदेशवासियों के हित के लिए पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई भी इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।



मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में समस्या का समाधान किया।

जनसुनवाई में फरियादी नगर निगम, जेडीए, गृह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,

जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। कोई परिवादी बीमारी में इलाज की मदद के लिए आते हैं तो कोई परिवादी अपनी पेंशन से जुड़े प्रकरण

को निस्तारण के लिए तो कोई विद्युत कृषि कनेक्शन के लिए। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर रहे हैं जिससे आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

कोटपूतली के नारायणपुर तहसील निवासी जयराम किसान परिवार से हैं। उन्होंने कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जोकि पिछले काफी समय से लंबित था। जनसुनवाई में अपने इस प्रकरण को लेकर जब जयराम आए तो मुख्यमंत्री ने फसलों के सीजन को देखते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जयराम के कृषि कनेक्शन आवेदन को प्राथमिकता से लेते हुए कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। इसी तरह अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील के कैलाश चंद मीणा को भी कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में फसलों की सिंचाई नहीं होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जनसुनवाई में मुख्यमंत्री को अपनी इस परेशानी से अवगत कराया।

कुमावत को एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड-हॉक कमेटी के क-वीनर के तौर पर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति करने पर सहकारिता रजिस्ट्रार, आरसीए और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सवार माधोपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक

27 जून को दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एड-हॉक कमेटी का क-वीनर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ है। एड-हॉक कमेटी का कंवीनर वह व्यक्ति ही बन सकता है, जो आरसीए चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो। दीन दयाल कुमावत का सवाई माधोपुर से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे ना तो सवाई माधोपुर में जन्मे और ना ही वहां निवास करते हैं। वे सवाई माधोपुर

के किसी प्राइमरी क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी भी नहीं हैं। ऐसे में वे जिला संघ के किसी पद के लिए भी पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें एड-हॉक कमेटी का कंवीनर बनाया गया है। इसलिए उनके नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों और दीनदयाल कुमावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करे सरकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को कहा है कि वह भारतीय नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कानून की समीक्षा करे और जरूरत पड़ने पर उन्हें संशोधित करने पर विचार करे। अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अनूठी परिस्थिति में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जस्टिस अनूप कुमार डंड की एकलपीठ ने यह आदेश सेहर गंगिया के अपने पिता के जरिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढ़ाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

याचिका में कहा गया कि उसके माता-पिता का मार्च, 2018 में विवाह हुआ था। इसके बाद वे आस्ट्रेलिया गए थे। जहां 1 जून, 2020 को याचिकाकर्ता का जन्म हुआ। इस पर वहां की सरकार ने नवंबर, 2021 में

- अदालत ने कहा कि इमिग्रेशन ब्यूरो याचिकाकर्ता की मां की एनओसी के बिना उसकी वीजा अवधि अधिकतम समय के लिए बढ़ाई। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता ब्यूरो में ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**
- याचिकाकर्ता पांच साल की बच्ची है और उसे ऑस्ट्रेलिया निवासित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**

याचिकाकर्ता को नागरिकता दे दी। इसके बाद वह भारत सरकार से वीजा लेकर अपने माता-पिता के साथ यहां आ गईं। इस दौरान उसकी समय-समय पर वीजा अवधि 24 जनवरी, 2024 तक बढ़ाई गई। याचिका में कहा गया कि इस बीच याचिकाकर्ता के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद पैदा हो गया और उसकी मां ने याचिकाकर्ता के पिता पर कई केस कर दिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इमिग्रेशन ब्यूरो में याचिकाकर्ता की वीजा अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसे ब्यूरो ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसकी मां ने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए एनओसी नहीं दी। ऐसे में याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसे अवैध प्रवासी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की

जाएगी। इसलिए मामले में कोर्ट दखल देकर उसकी वीजा अवधि बढ़ाए। इसका विरोध करते हुए इमिग्रेशन ब्यूरो की ओर से अभी तक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ कई दंडात्मक कार्रवाई या उसे डिपोर्ट नहीं कर रहा है। ब्यूरो की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है और उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए।

शिक्षा के साथ संस्कारों की सीख दे रहा है गायत्री परिवार: दिलावर

जयपुर। किरण पथ, मानसरोवर स्थित गायत्री वेदना निवारण केंद्र परिसर में मां भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रवेशोत्सव- 2025 बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे। उन्होंने मां गायत्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वालित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिलावर ने कहा कि गायत्री परिवार के इस विद्यालय ने बहुत कम समय में अच्छी तरक्की की है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार भी प्रदान कर रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय का शुभारंभ मेरे द्वारा हुआ था तथा आज प्रवेश उत्सव भी मेरी उपस्थिति में हो रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार सामाजिक एवं राष्ट्रहित के कामों में सदा अग्रणी रहता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि गायत्री परिवार सदैव समाज एवं राष्ट्र के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजकीय विद्यालय में बड़ी तेजी से नामांकन व वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए गुणात्मक प्रयास एवं नवाचारों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। बच्चों ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के



गायत्री परिवार के मां भगवती विद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों का प्रवेश उत्सव मनाया।

साथ शिक्षा मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। शिक्षा मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी सहित अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी एवं राजस्थान जोन समन्वयक ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि यह विद्यालय गायत्री परिवार द्वारा नि:शुल्क संचालित किया जा रहा है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में

नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा व स्टाफिंग में खामियों को लेकर नोटिस जारी

आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी

जयपुर/जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. भाटी और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा शामिल हैं, ने देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में सुरक्षा, स्टाफिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नवोदय विद्यालय समिति को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अधिवक्ता विनीत आर. दवे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कई नवोदय विद्यालयों में अब तक पूर्णकालिक वार्डन, काउंसलर, सीसीटीवी निगरानी, परिधि सुरक्षा, आपात प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। जबकि शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एनसीपीसीआर, एनडीएमए द्वारा इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई चौंकाने वाले तथ्य को उजागर

- जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं**
- विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे आधारभूत ढांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है**

किया है जैसे कि दिसम्बर 2024 की शिक्षा के क्षेत्र में संसद की खासी समिति को भी उद्धृत किया है जिसके अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय में 6800 से भी अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पद खाली पड़े है। यानी इन विद्यालयों में 24.77 प्रतिशत पदो की रिक्तियों को भरा नहीं गया है जबकि कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि रिक्तियों को जल्द भरा जाये। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2019 में जारी एक परिपत्र के माध्यम से सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को

अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 147 छात्रों ने आत्महत्या की थी। आरटीआई से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से 2017 के बिच ही इन विद्यालयों में 49 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें से आधे एसएसी -एसटी वर्ग के थे। वही 2019 से 2023 के बीच 25 छात्रो ने आत्महत्या की, जिसमें भी एक बड़ा हिस्सा एसएसी -एसटी वर्ग का था। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्यादातर इन मौतों में कई मामलों में एफआईआर दर्ज है परन्तु कई मामलों में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इन विद्यालयों में साफ सफाई, सुरक्षा, टुटे-फुटे आधारभूत ढांचे और अन्य कई तरह की मानसिक परेशानीयो से छात्रों को झुझना पड़ता है, और आये दिन इन मुद्दो पर प्रदर्शन किये जाते हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं।

विवाद बढ़ा तो ठेकेदारों ने 20 प्रतिशत रेट घटाकर ले लिया पौधे सप्लाई का टैंडर

- कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर निगम में पौधे सप्लाई के टैंडर में भारी गड़बड़झाला चल रहा है। "वन टाइम प्लान्टेशन" के लिए 10 फ़ीट पौधे देने के लिए ठेकेदारों ने पहले तो मात्र 5 प्रतिशत कम रेट डाली थी, परन्तु हैरिटेज निगम में 55 प्रतिशत कम दर आने के बाद जब विवाद बढ़ा तो इन्ही फर्मों ने अपनी रेट 20 प्रतिशत तक घटाकर काम ले लिया।

अब चर्चाएं यह हो रही हैं कि आखिर हैरिटेज निगम से 35 फ़ीसदी ज्यादा कीमत पर पौधे खरीदने के लिए ग्रेटर निगम के अफसर उत्सुक क्यों हैं? वह भी उस स्थिति में जब अधिकांश ठेके एक ही फर्म मैसर्स जसवाल बिल्डर्स के नाम पर छूटे हैं। हालाँकि उद्यान शाखा के अफसरों का कहना है कि 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर पौधे उपलब्ध

करवाना संभव ही नहीं है। परन्तु सवाल यह उठ रहा है कि यह चिंता तो कम दर पर ठेके लेने वाले संवेदक को होनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर निगम प्रशासन ने वन टाइम प्लान्टेशन कि निविदा के कार्यदेश "नेगोशिएशन" के बाद 20 प्रतिशत कम दर पर जारी किये हैं। यहाँ ठेकेदार ने 300 रुपए के 10 फीट के पेड़ 270 से 285 रुपए तक में देने की दर डाली थी, परन्तु जब हैरिटेज निगम में आधी कीमत यानी कि 135 से 150 रुपए तक की रेट आयी तो बड़ा विवाद हो गया। तमाम विवादों के बावजूद ग्रेटर निगम प्रशासन ने यह कार्यादेश जारी करने का फैसला लिया। मजदार बात यह है कि जेडीए प्रशासन ने भी यही संवेदकों से 160 से 170 रुपए के बीच खरीदे है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे है कि आखिर

ग्रेटर निगम प्रशासन ही जानबूझकर लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान क्यों झेलने पर उतारू है। जबकि तीनों विभागों ने पौधों की एक समान खरीद दर 300 रुपए तय की थी। जिसमें नीम, शीशम, करंज, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, चंपा, आवला, सीताफल, खेजड़ी, अर्जुन, बालम खेड़ा, कनेर, हरसिंगार, शहतूत, अमरूद, पीपल, जामुन, बेलपत्र, गुड़हल, मौलश्री, चंदन और आम के पेड़ शामिल हैं।

सूत्रों की माने तो ग्रेटर नगर निगम की उद्यान शाखा ने इस बार "वन टाइम प्लान्टेशन" के 30 लाख रुपए से कम के टैंडर में भी कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी थी, जिसके कारण "डी" श्रेणी के ठेकेदार चाहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस कारण इन निविदाओं में सिर्फ चुनिंदा फर्मों ने ही भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 35 फ्रीसदी ज्यादा कीमत पर पौधे खरीदने के लिए ग्रेटर निगम के अफसर उत्सुक क्यों हैं? वह भी उस स्थिति में जब अधिकांश ठेके एक ही फर्म मैसर्स जसवाल बिल्डर्स के नाम पर छूटे हैं। हालाँकि उद्यान शाखा के अफसरों का कहना है कि 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर पौधे उपलब्ध

भाजपा रक्षाबंधन पर्व को सेवा, संगठन और समर्पण के रूप में मनाएगी

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी आगामी 8 से 10 अगस्त तक पूरे राजस्थान में रक्षाबंधन पर्व को जनसहभागिता, संगठनात्मक सहभागिता एवं सामाजिक समर्पण के साथ भव्य रूप में मनाने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता "रक्षा का यह पर्व, सामाजिक एकता और सेवा का अवसर" के मूलभाव के साथ जिलों, विधानसभाओं और मंडलों में समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाएंगे।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान संयोजक मुकेश दाधीच ने बताया कि प्रत्येक जिले में एक जिला महामंत्री एवं महिला मोर्चा की दो पदाधिकारी संयोजक व सह प्रोजेक्ट के रूप में कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

8 अगस्त को सम्मान व समर्पण दिवस:

इस दिन पार्टी कार्यकर्ता टैफिक पुलिस, अस्पताल स्टाफ, विद्यालयों, सरकारी व निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों सहित सेवाभावी कर्मियों को राखी बांधकर आभार प्रकट करेंगे। बहनों द्वारा तिलक, राखी एवं मिष्ठान वितरण कर यह संदेश दिया जाएगा— आप हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं।

स्थानीय मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेवा भावना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

9 अगस्त को संगठनात्मक एकता

व परिवार दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता इस दिन अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाएंगे और बुध, मंडल, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन के सदस्यों के बीच भाईचारे का पर्व मनाकर भाजपा परिवार – एक सूत्र में बंधा, संकल्पित भारत के लिए समर्पित भाव का संशक्त करेंगे।

10 अगस्त को सेवा व सामाजिक सद्भाव दिवस को भाजपा कार्यकर्ता सीमाओं पर तैनात सैनिकों की राखी भेजेंगे या उनके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। साथ ही कच्ची बस्तियां, मजदूर बस्तियां, झुग्गी-झोपडियों और घुमंठू समाज के बीच जाकर राखी व मिठाई वितरित की जाएगी। यह दिन "रक्षा का धागा, सम्मान और अपनत्व का संदेश" लेकर सेवा और संवेदना का उत्सव बनेगा।

यह आयोजन सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों की सहभागिता से जिले, विधानसभा एवं मंडल स्तर पर आयोजित होगा। पूर्व तैयारी बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।

भाजपा का उद्देश्य रक्षाबंधन को सेवा, संगठन और समर्पण के पर्व के रूप में जन-जन तक पहुंचाना है।

रक्षा सूत्र से बंधेगा भारत, एकता, सेवा और संस्कारों के साथ – यही है इस कार्यक्रम की मूल भावना।

जयपुर स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ. निधि पटेल ने की समीक्षा बैठक

जयपुर। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ निधि पटेल ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की नियमित माॉनिटिंग करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि स्मार्ट सिटी में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कैमरों से कचरा फैकने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए।

जिससे कि सड़क पर कचरा फैकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीईओ निधि पटेल ने कहा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि शहर के प्रमुख बाजारों में देर रात तक खुलने वाली दुकानों से कचरा सड़क पर ही फैका जा रहा है, जो कि सुबह तक सड़क पर ही पड़ा रहता है और ओपन डिपो का रूप लेकर शहर में सफाई व्यवस्था को खराब कर रहा है। इसलिए एगिनिगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारी मिलकर दोस प्लानिंग करें और उन दुकानों को चिह्नित कर समझाइश करें नहीं मानने पर भारी



जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ डॉ. निधि पटेल ने बुधवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की।

चालान वसूला जाए। जिससे कि सफाई व्यवस्था बेहतर हो। वहीं समीक्षा बैठक के दौरान सीईओ निधि पटेल ने स्मार्ट सिटी के प्रगतिरत प्रोजेक्ट को समीक्षा की और कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही लाल ड्रंगरी कचरा ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण को लिए अपआएफ प्लॉट के शुरू होने के लिए शीघ्र पॉल्यूशन पुनओसी लेने और लंगडियावास में पौधरोपण करने के निर्देश दिए।समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी के अधिकारी और नगर निगम हेरिटेज के जोन उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बाजारों में कचरा संग्रहण के लिए चल रहे निगम के हूपर, व्यापारी हूपर में ही डालें कचरा वहाँ, सीईओ डॉ निधि पटेल ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज की ओर से समयानुकूल सभी बाजारों में हूपर चल रहे हैं। दुकानदार अपने कचरे को हूपर में ही डालें, सड़क पर कचरा नहीं फैलाए, जिससे कि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो।

रक्षा सूत्र कार्यक्रम में डॉ. सतीश पूनियां को आदिवासी बहन-बेटियों ने राखी बांधी

सतीश पूनियां ने हजारों आदिवासी माता-बहनों के साथ राखी का पर्व मनाया

जयपुर/डूंगरपुर।मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के आदिवासी अंचल के डूंगरपुर जिले में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में रक्षा सूत्र कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सकारात्मक तौर पर भाजपा की वागड़ क्षेत्र में मजबूती के तौर पर चर्चाओं में है। इस ऐतिहासिक रक्षा सूत्र कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा हरियाणा संगठन प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां राजस्थान के वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर पहुंचे, जहां काफी संख्या में जनजाति माता-बहनों ने उन्हें राखी बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उन्नित का आशीर्वाद दिया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व राज्यमंत्री सुशील कटारा द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्षाम्त्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एक हजार से अधिक बहनों ने सतीश पूनिया एवं सुशील कटारा को राखी बांधी। कार्यक्रम मे सागवाडा विधायक शंकरलाल देवा, जिलाध्यक्ष अशोल पटेल, सभापति अमृत कलासुआ, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अरुका मूंढडा इत्यादि नेता व कार्यकर्ता

- डूंगरपुर में रक्षा सूत्र कार्यक्रम में माता-बहनों ने डॉ. सतीश पूनियां को अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उन्नित का आशीर्वाद दिया**

कार्यक्रम में मौजूद रहे।

डॉ. सतीश पूनियां ने संबोधित करते हुये कहा कि, पहले बेटियों को अभिशाप की तरह मानते थे, किसी जमाने में बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, लेकिन मैं यह मानता हूं जिसने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, उनको बेटी नसीब होती है। मैं खुशनसीब हूं क्योंकि बेटी एक पिता का सबसे बड़ा संबल होती है। उन्होंने कहा कि, एक बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो दुनिया के बड़े-बड़े आशीर्वाद फोके पड़ जाते हैं, एक मां भले ही उम्रदराज होगी मैं भी देखता हूं कि मेरी १5 वर्षीय मां जब मेरे सिर पर हाथ फेरती है तो मुझे लगता है कि

दुनिया की सलतनत मुझे मिल गई, मातृशक्ति किसी भी रूप में हो, जब मैं चुनौतियों से लड़ता था मेरे घर का चूल्हा जलाने का काम और विपरीत परिस्थितियों में मेरे पीछे डटकर खड़े होने वाली कोई थी वह मेरी धर्मपत्नी थी।

पूनियां ने कहा कि,दुनिया में वह हमारा आदिवासी समाज है जो जल जंगल और जमीन को रक्षा करता है, दुनिया ने यह नारा बहुत देर से लगाया लेकिन हमारा आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण करता आया है, राजस्थान और हिंदुस्तान का इतिहास है कि पेड़ों के रक्षा के लिए अमृता देवी शहीद हो गई, यह वर्षों पुरानी परंपरा है। मुझे सुखद अनुभूति और बहुत खुशी हुई कि हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियां पढ़ लिखकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, और इन्हीं आदिवासी माता बहनों का आज रक्षा सूत्र कार्यक्रम में राखी के रूप में मुझे जो आशीर्वाद मिला वह मुझे नई ऊर्जा और ताकत के साथ कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।



भाजपा हरियाणा संगठन प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां को डूंगरपुर में जनजाति माता-बहनों ने राखी बांधकर आशीर्वाद दिया।

डीडवाना में मिलावटी खाद्य सामग्री पर कार्रवाई

डीडवाना, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड्गनावत के निर्देश पर आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएं जाने के लिए अभियान के तहत रक्षाबंधन त्योहार के महानेजर रखते हुए जिले में कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को डीडवाना में जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुल्हार, प्रवर्तन निरीक्षक विंदेश खड्गड़ व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल की संयुक्त टीम ने रिलायंस मॉल, मित्तल सेल्स, आधार मार्ट व समृद्धि बाजार का निरीक्षण कर खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, साफ-सफाई एवं खाद्य सामग्री पर पैकेजिंग तिथि तथा उपयोग दिनांक की जांच की।

इस दौरान मॉल मित्तल सेल्स एवं

रिलायंस स्टोर से अवधिपार खाद्य सामग्री जैसे गेहूं का आटा, बिस्कुट, मिसस सूप, पापड़, हल्दी आदि मिली जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया तथा फर्म को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 32 का इम्पूव नोटिस दिया गया। वहीं काबू, किशमिश, अंजीर व बादाम के नमूने एवं मेसर्स रिलायंस मॉल से धी का नमूना और श्री बालाजी दूध एंड मावा भंडार से 10 लीटर दही नष्ट करवाया गया और धी का नमुना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

मीरा महोत्सव का समापन

मेड़ता सिटी, (निसं)। 521वें मीरा जयंती महोत्सव का रजत रेवाड़ी की शोलायना निकाकर समारपन किया गया। मीरा महोत्सव समिति के सचिव रविप्रकाश कमेडिया ने बताया कि रजत रेवाड़ी चारभुजानाथ मंदिर से प्रारंभ होकर सब्जी मंदिर, पड़ाव होते हुये शहर के मुख्य मार्गों से होते पुनः चारभुजानाथ मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। महोत्सव के समापन की पूर्व संध्या पर राजस्थान प्रांत प्रचारक निंबाराम ने

कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं भजन

गायक प्रकाश माली ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर विधायक लक्ष्मणराम कलरू, उपखंड अधिकारी पूनम चोपल, तहसीलदार रामसिंह गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष पवन परतानी, महोत्सव समिति अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, श्याम तिवाड़ी, जगदीश नारायण शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाम डाक, विनोद भाटी, नारायण पारिक, अभिमन्यु शर्मा, रवि गहलोत, कैलाश गौड़, राजू भाई माली सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

एलिवेटेड रोड के पिलर से पिकअप मिनी कंटेनर टकराया

अजमेर, (कासं)। स्टेशन रोड माल गोदाम के सामने बुधवार दोपहर एक पिकअप मिनी कंटेनर एलिवेटेड रोड के पाइलिंग पिथर से टकरा गया। कंटेनर के ठीक पीछे चल रहा ट्रैपो भी अचानक ब्रेक लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। दोनों वाहनों के चालकों के चोटें आई हैं। घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन मंगारकर वाहन को साइड में कराया और यातायात को सुचारु किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिथर की क्लीयरेंस हाइट कम है और जगह-जगह ऊंचाई संकेतक-चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ड्राइवर पिथर की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए अक्सर ऐसे टच-डाउन हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि चालक वाहन को मोड़ने के लिए जैसे ही पिथर के करीब आया और एकाएक ऊंचाई का अनुमान नहीं लगा पाया।

अनिवार्य रूप से गुहाला जेईएन ऑफिस में बैठने की व्यवस्था की जाए नांगल तक चलने वाले हस्ताक्षर अभियान की घोषणा की है। घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आठ अपरास्त की नीमकाथाना ग्रामीण एईएन कार्यालय का

परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन

- बीकानेर**, (निसं)। सरकारी स्कूल के लेक्चरर (टीचर) ने 11 बों की छात्रा को लव लेटर दे दिया। छात्रा ने इसकी जानकारी परिजन को दी तो हंगामा हो गया। छात्रा के पेरेंट्स और ग्रामीण बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे। स्कूल के गेट को ताला लगाकर प्रदर्शन किया।

हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी किशनदान चारण ने लेक्चरर को सम्पेंड कर दिया। टीचर का मुख्यालय भी दूंगरपुर कर दिया है। मामला

घेराव भी प्रस्तावित है।

ओमप्रकाश सैनी और विजय सिंह गजराज के नेतृत्व में 18 सदस्यीय बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का गठन किया गया, जो आगामी अंदोलनों की रणनीति तय करेगी। धरने में कॉ.



फरार हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे शातिर बदमाश और हिस्ट्रीशीटर कुंदन जाट को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया है कि आरोपी कुंदन जाट थाना सदर क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है और गंभीर वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया है की बीती 10 जुलाई को सरसिया निवासी नरेश कुमार मीणा आनन्दा होटल पर बैठर का काम कर रहा था। उसी दौरान निलेश बलाई, खाना कीर व 5-6 अन्य आरोपी वहां आए और खाने के बाद भुगतान मांगने पर जातिगत अपमान करते हुए उसके साथ लाठी, डंडों और लात-धुंसे से जानलेवा हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट आने से प्राथी लहलुहाहन हो गया। आरोपी जाते-जाते जान से मारने और होटल में आग लगाने की धमकी भी दे गए। इसको लेकर पीडित की रिपोर्ट पर पुलिस ने



पुलिस ने शातिर बदमाश कुंदन जाट को गिरफ्तार किया।

मामला कर जांच शुरू की, जिसके बाद एक आरोपी खाना उर्फ कन्हैयालाल कीर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं आरोपी कुंदन जाट फरार था। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर मुखबिरों की मदद से कुंदन की लोकेशन ट्रैस की और सदर थाना पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस पृष्ठताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया, जिसके बाद उसे

कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा

गया। पुलिस टीम में पुलिस उपाधीक्षक

रविंद कुमार सहित थानाधिकारी महावीर

प्रसाद मीणा शामिल रहे। पुलिस ने बताया

कि आरोपी कुंदन जाट एक आदतन

अपराधी है, जिसके खिलाफ पुलिस

थाना सदर में 11 संगीन अपराधिक

प्रकरण दर्ज हैं और थाने का घोषित

हिस्ट्रीशीटर है।

प्ले स्कूल की बिल्डिंग में आग लगी, बड़ा हादसा टला

- हादसे के समय नन्हें-मुन्ने बच्चे क्लास रूम में बैठकर खाना खा रहे थे**
- कुछ ही देर में धुआं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में फैल गया**
- गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई भी बच्चा हताहत नहीं हुआ, सभी सुरक्षित**

लगे तो कुछ घबराहत में अपने बैग और टिफिन छोड़कर बाहर की ओर भागे। स्कूल स्टाफ ने बच्चों को तुरंत कक्षाओं से सुरक्षित बाहर निकाला और पास के एक मकान में शिफ्ट किया। इसी बीच सूचना मिलते ही दो दमकलों मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने ऊपरी मंजिल पर लगी आग पर काबू पाया। स्कूल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की मदद के लिए आस पास रहने वाले लोग भी पहुंच गए और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

खबर मिलते ही अभिभावक बदवास हाउस में स्कूल की ओर दौड़ पड़े। कई लोग अपने बच्चों का नाम पुकारते हुए गलियारों में उन्हें तलाशते दिखे। एक महिला अभिभावक ने अपने बच्चों की संकुशल देखकर अपने आंसू पोछते हुए कहा कि स्कूल से हमारा घर

काफी दूर है। जैसे ही आग की बात सुनी

तो उनका ब्वाड प्रेशर बढ़ गया, हाथ कांपने

लगे। रास्ते भर सिर्फ यही डर था कि बच्चे

के पास कब तक पहुंच पाऊंगा। कई

परिजनों ने राहत की सांस लेते अपने-

अपने बच्चों को गले लगा लिया। हैरानी

की बात यह ही कि स्कूल प्रबंधन का रवैया

अभिभावकों के प्रति रूखा नजर आया।

बिल्डिंग मलिक डॉ. रंजीता तवर

का कहना है कि बिल्डिंग की तीसरी

मंजिल पर घर है। शॉर्ट सर्किट होने पर

आग मंदिर में लग गई थी, जिससे तुरंत

भागते हुए नीचे पहुंची और स्कूल के

पास के बच्चों को बाहर निकालकर पास

के कैंपस में भिजवा दिया था। स्टाफ को

भी बाहर निकाल गया, सभी बच्चे

सुरक्षित हैं। घर के अंदर नुकसान हुआ

है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा

लिया था।

मावा कारखाने पर पकड़ा 350 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया

- टीम ने रिफाईंड तेल के पीपे, एसएनएफ पाउडर, मिल्क पाउडर के कट्टे बरामद किए**
- जांच के दौरान परिसर में भारी गंदगी मिली और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर परिसर को सील कर दिया**

के लिए बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम हमीराका, तहसील तिजारा में छापा मारा। मौके पर आरिफ खान द्वारा मावा बनाने के लिए दूध में मिलावट की जा रही थी। टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से मौके पर ही दूध की जांच की, जिसमें आंशिक मिलावट की पुष्टि हुई। छापे के दौरान रिफाईंड तेल के पीपे, एसएनएफ पाउडर, मिल्क पाउडर के कट्टे बरामद किए गए। ये सभी सामग्री दूध में मिलावट और फैट बढ़ाने के लिए

उपयोग की जाती है। मौके से लिए गए

दूध और मावा के नमूने खाद्य

प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं, मिलावटी

व बदबूदार दूध को मौके पर ही नष्ट कर

दिया गया। जांच के दौरान परिसर में

भारी गंदगी पाई गई और खाद्य सुरक्षा

मानकों का पालन नहीं किया जा रहा

था, जिसके चलते परिसर को सील कर

दिया गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा

अधिकारी हेमंत कुमार, उजीनरीक्षक

लोकेश (थाना अधिकारी), शेखपुर

(अहीर), महिपाल सिंह, सुभाष यादव,

रमेश शर्मा, हेमराज, सुंदर सहित टीम

के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

स्मार्ट मीटर लगाने विरोध जारी

डीडवाना, (निसं)। प्रदेशभर में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को लाडनूं विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया साथ ही कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड्गनावत को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। विधायक मुकेश भाकर ने उपभोक्ताओं के घरों में जबरन बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए कहा कि बिजली कंपनियां केंद्र सरकार व राज्य सरकार के इशारे पर स्मार्ट मीटर लगा रही हैं, जबकि सभी उपभोक्ताओं के घरों में पहले से ही डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि यह कदम

अनावश्यक है, जिससे कराड़ों मीटर बर्बाद होंगे और अरबों रुपये के स्मार्ट मीटर लगाकर कंपनियों व ठेकेदारों को जेबें भरी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर अब खुली छूट को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन किसान वर्ग इसका पूर्ण विरोध करेगा।

- प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर के गरीब किसान, मजदूर और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा हमला बताया**

ओमप्रकाश यादव, रोशन लाल गुर्जर, सुरेंद्र खोखर, फूलचंद सैनी, जेपी वर्मा, गणपत राम मिठारवाल, पवन मील सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। ज्ञापन की मुख्य मांगें जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने की योजना रद्द हो, बिजली निजीकरण पर रोक लगे, जेईएन गुहाला की गुहाला जेईएन ऑफिस में बैठने की व्यवस्था हो, गुहाला जीएसएस को चौकड़ी से जोड़ा जाए, क्षतिग्रस्त और रास्ते में खड़े खंभे हटाए जाएं, अयोषित बिजली कटौती बंद हो। धरने में श्रवण यादव, हरसिंह कुड़ी, कैलाश सैनी, रमेश सैनी, सुरेश सैनी, शिवराम लॉबा, सुबेदार रामकुमार आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।

पाटन, (निसं)। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने सहायक अभियंता कार्यालय चला पर धरना प्रदर्शन किया। धरने में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों, किसानों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटरों की अनिवार्यता, अयोषित कटौती और क्षेत्रीय समस्याओं के खिलाफ छह सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सीपा। सभा की अध्यक्षता पूर्व सरपंच बीरबल काजला व जगदीश सैनी ने की, जबकि संचालन ओमप्रकाश सैनी (संयोजक, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति) ने किया।

माकपा सचिव कॉ. गोपाल सैनी ने

कहा कि स्मार्ट मीटर गरीब किसान,

मजदूर और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं

की जेब पर सीधा हमला है। इसे अडानी-

अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने

के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी

दी कि यदि ठेकेदार के कर्मचारी जबरन

स्मार्ट मीटर लगाने गांव आए, तो जनता

उन्हें वापस लौटा देगी। सभा में वक्ताओं

ने मांग की कि जेईएन गुहाला को



माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने के लिए डीपीआर बनेगी

सात हजार करोड़ रूपए की परियोजना से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर की पेयजल समस्या का स्थाई निदान होगा

जयपुर, 6 अगस्त। पाली, जालोर, सिरोही बाड़मेर में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब मूर्त रूप लेगा। इस विषय को लेकर सुमरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में सात हजार करोड़

- मुख्यमंत्री भजनलाल, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने परियोजना के बारे में विस्तार से ब्रीफ किया।
- वाफ़ोस ने परियोजना की इन्सपैक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग को सौंपी।

रूपए के इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माही एवं सोम नदी का मानसून अवधि का अधिशेष जल, जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जवाई बांध तक लाने संबंधी कार्य की, 2024–25 के बजट में घोषणा की थी। इस



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बुधवार को सुमेरपुर विधायक व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने एक बैठक में माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाले सात हजार करोड़ रूपए के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा की।

परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए 15.60 करोड़ रूपए की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति जल संसाधान विभाग, जयपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियंता, जल संसाधान खंड सलूंवर ने

वाफ़ोस लिमिटेड से अनुबंध कर कार्यदेश भी जारी कर दिए। इसके बाद वाफ़ोस द्वारा इन्सपेक्शन रिपोर्ट जल संसाधन संभाग, उदयपुर को प्रस्तुत किये जाने के बाद विभाग ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है।

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने

बताया कि सात हजार करोड़ रूपए का यह महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा होने पर उदयपुर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर जिले में पेयजल संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही, 16 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का पुर्नस्थापन होगा।

सीजेआई गवई का सीनियर वकीलों को अल्टीमेटम

नई दिल्ली, 06 अगस्त। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई ने बुधवार, 6 अगस्त 2025 को साफ कर दिया कि 11 अगस्त से कोई भी सीनियर वकील उनकी अदालत में तत्काल सुनवाई के लिए मामले नहीं ला सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका मिल सके।

सीजेआई गवई ने वकीलों की ओर से तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई

- गवई ने कहा, 11 अगस्त से मेरे कोर्ट में कोई भी सीनियर वकील तत्काल सुनवाई के लिए केस नहीं ला सकेगा।

के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया था, जिसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बंद कर दिया था।

सीजेआई गवई ने कहा, “इस बात की पुर्खोर मांग उठ रही है कि सीनियर वकीलों को किसी भी मामले में तत्काल सुनवाई के लिए मेशन न किया जाए।”

उन्होंने अदालत के कर्मचारियों से कहा कि वे एक नोटिस जारी करें कि सोमवार से उनकी अदालत में किसी भी वरिष्ठ वकील को तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई के लिए मामलों का लाने की इजाजत नहीं होगी।

सीजेआई ने कहा सोमवार से किसी भी सीनियर वकील, किसी भी नामित सीनियर वकील को मामलों का उल्लेख करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जूनियर वकीलों को ऐसा करने का मौका दिया जाना चाहिए।

मैडिकल बोर्ड में 29 में से 24 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट निकले

- एसओजी ने दिव्यांगत प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया।
- सबसे ज्यादा अनफिट कर्मचारी श्रव्य बाधित श्रेणी में पाए गए।

जयपुर, 6 अगस्त । एसओजी ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। एसओजी पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली कि विगत समय से विभिन्न सरकारी नौकरियों में अनेक चयनित उम्मीदवारों ने दिव्यांग नहीं होते हुए भी फर्जी तरीके से बनवाया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है।

सूचना मिलने के बाद एसओजी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मोणा के नेतृत्व में जांच दल गठित कर एसएमएस मैडिकल कॉलेज के विभिन्न विशेषज्ञों का बोर्ड गठित करवा कर दिव्यांग श्रेणी के लोक सेवकों की पुनः मैडिकल जांच करवाई गई, जिसमें 29 दिव्यांग लोक सेवकों की मैडिकल जांच कि रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें से मात्र 5 लोक सेवकों में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना पाया

गया और बाकी 24 तथाकथित दिव्यांगों को मैडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बताया। श्रव्यबाधित 13 में से 13 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए। दृष्टिबाधित तथाकथित 8 दिव्यांग में से 6 दिव्यांग कैटेगरी के नहीं पाए गए। इसी तरह लोकोमोटर एवं अन्य प्रकार के 8 लोक सेवकों में से 5 दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए।

अनफिट पाए गए लोक सेवक हैं- महेंद्र पाल पुत्र गिरधारी सिंह, तहसील पुलिस थाना भीम राजसमंद; सवाई सिंह गुर्जर टिगरिया का पुरा, हिण्डौन, करौली; हनुद गुर्जर चंदवाजी जयपुर; मनीष कुमार कटारा बरीली, रुपवास, भरतपुर; केशव उर्फ खूब्वाराम रेनवाल; कविता रेनवाल; बिकेश कुमार नदबई, भरतपुर; भानुप्रताप कटारा, रुपवास; नफीस जुहरार, भरतपुर; रणजीत सिंह बयाना, भरतपुर; कलुआ राम बयाना भरतपुर; पवन कुमार आबूरोड सिरौही; विनोद कंवर आबू रोड सिरौही; दिनेश कुमार, धौरीमन्ना बाड़मेर; लोकेश नदबई भरतपुर; संजय नौखा बीकानेर; दीपू डीडवाना, कुचामन; गैंगू बलूपुरा पाली; प्रशांत सिंह गांधी नगर सिरौही; हिन्दूपाल सिंह केसरीसिंहपुरा गंगानगर; आसी कुमारी मारुडी, बाड़मेर; डॉ शंकर लाल मीणा देवपुरा बूंदी; विद्याश चौधरी रुपनगढ़ जिला अजमेर; किशोर सिंह सबलपुर डीडवाना कुचामना

एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक बयान में बताया कि 1 अक्टूबर से एयर इंडिया के सभी इंटरनेशनल फ्लाइटों की आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक अक्टूबर से एयर इंडिया के इंटरनेशनल विमानों की आवाजाही 12 जून से पहले वाली स्थिति में आ जाएगी।

अहमदाबाद हार्दसे के बाद एयर इंडिया के, इंटरनेशनल के साथ-साथ, घरेलू विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा था। दुर्घटना के बाद, एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच लॉन्च रहने तक अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से रोक दिया था।

समुद्री माल परिवहन बिल पर संसद की मुहर

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। भारत से शेष दुनिया के समुद्री बंदगाहों तक माल ढ़लाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों और अधिकार तथा छूट से संबंधित प्रावधानों वाले समुद्री माल परिवहन विधेयक को बुधवार को राज्य सभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही, इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी। इस विधेयक को लोक सभा ने गत 28 मार्च को पारित किया था।

राज्य सभा में आज शुन्काल के दौरान पहले स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे कार्यवाही पुनः शुरू होने पर विपक्ष

के हंगामे के बीच पीठासीन उपसभापति भुवनेश्वर कलिता की अनुमति से मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहे मणिपुर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्यय का ब्यौरा रखा। हंगामे के बीच ही, विधायी कार्य के एजेंडा में पहले स्थान पर उल्लिखित समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पर चर्चा करायी गयी। इस विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के कतिपय संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज करने के बाद, विधेयक को बख़्त मतदान से अनुमोदित कर दिया गया।

विपक्ष ने संसदीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन झूठे दावों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है, जो संसद को सुचारु रूप से चलने से रोक रहे हैं।”

गोगोई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि 1961 में राज्यसभा में चुनाव आचार संहिता के नियमों में संशोधन पर बहस हुई थी, उस चर्चा का नेतृत्व उस समय के कानून मंत्री गोपाल पण्डित ने किया था। गोगोई ने बताया कि 1981 में, कांग्रेस सांसद मनुभाई पटेल ने चुनावी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस सांसद ने कहा, “1991 में, राज्यसभा में मौजूदा चुनावी कानूनों में संशोधन की तत्काल आवश्यकता पर बहस हुई। 2015 में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए

प्रॉक्सी और ई-पोस्टल वोटिंग पर “कॉलिंग अटेंशन मोशन” प्रस्तुत किया था। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने विपक्ष की राय को मानने की बात स्वीकार की।”

गोगोई ने कहा कि हाल ही में, 2019 में भी चुनावी सुधारों पर “अल्पकालिक चर्चा” हुई थी, जिसमें तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। सरकार को इस लंबे समय से लंबित और आवश्यक बहस में देरी नहीं करनी चाहिए।

गोगोई ने कहा, “आइए, संसद में चुनावी सुधारों पर चर्चा करें।” रमेश ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि 1986 में भी व्यापक चुनावी सुधारों की आवश्यकता और संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने पर चर्चा हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू की “विद यू स्टालिन” योजना को हरी झंडी दी

नयी दिल्ली, 06 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की “विद यू स्टालिन” योजना में वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम के इस्तेमाल पर रोक वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को रद्द दिया।

इसके साथ ही अदालत ने सरकारी योजना के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अन्नाद्रमुक सांसद सी.वी. धनमुगम पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन बी अंजारिया की पीठ ने उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए, उसके खिलाफ राज्य सरकार और द्रविड़ मुनेत्र कडगम (द्रमुक) पार्टी की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा, हमने बार-बार कहा है कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक हिंसा-खिलाफ निपटारने के लिए किया जाना चाहिए। इस आदेश के साथ ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की विद यू स्टालिन योजना हरी झंडी दे दी।

‘अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए राज्य सरकारें चार हफ्ते में अधिसूचनाएं जारी करें’

- सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को, कमजोर वर्गों को शिक्षा के लिए दिए गए 25 प्रतिशत कोटा में शामिल करने के निर्देश दिए

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और

उत्तरकाशी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के जगह-जगह अवरोध हो जाने के कारण अनेक वाहन अब भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हर्षित स्थित सेना के कैंप में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र में लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे खोज और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि मृतकों के आँकड़े में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। उत्तरकाशी इस समय हाल के वर्षों की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है।

- सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को, कमजोर वर्गों को शिक्षा के लिए दिए गए 25 प्रतिशत कोटा में शामिल करने के निर्देश दिए

न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने अधिवक्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही अनाथ बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बाकी राज्य भी इस संबंध में प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी कर लें। शीर्ष अदालत ने राज्यों को उन अनाथ बच्चों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया। जिन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया गया है और जिन्हें दाखिले से मना कर दिया गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संबंधित सर्वेक्षण में दाखिले से इनकार करने के कारण दर्ज किये जाएं।

ट्रंप ने भारत पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की धमकियों के आगे झुकने से दृढ़ता से इनकार कर दिया है। “इस बात को स्वीकार करो या नहीं”, भारत अब दुनिया की प्रमुख भू-राजनीतिक शक्तियों के क्लब में आ गया है और इस पोजीशन के लिए कीमत तो भारत को चुकानी ही पड़ेगी। जब भारतीय नियत अमेरिकी बाजारों से बाहर हो जाएंगे, तो भारत को दूसरे बाजार तलाशने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

जहाँ एक तरफ भारत के अडिग रुख और अस्थिर स्वभाव वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे झुकने से इन्कार करने की कुछ हल्की सराहना जरूर हो रही है, वहीं, प्रतिक्रियाएं कुछ दबी-दबी हैं, सिवाय व्यापार और भू-राजनीति के, जो अब पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़ चुके हैं।

ट्रंप के विशेष दूत स्टीव बिट्कोफ इस समय मॉस्को में पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और मंगलवार को दोनों की मुलाकात को क्रेमलिन के प्रवक्ता ने “रचनात्मक” बताया है। भारत, ट्रंप की रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का पहला “भू-राजनीतिक शिकार” बन गया है। भारत की स्थिति यह हो गई है कि

वह अब रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, ऐसा करना बहुत अधिक झुकना होगा और भारत के अपने हितों को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिकी को होने वाले निर्यात में कुछ असर पड़ने की तुलना में, तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना भारत के लिए एक ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आखिरकार, अमेरिकी निर्यात भारत की समग्र अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा हिस्सा है और भारत की अर्थव्यवस्था उतनी निर्यात-निर्भर नहीं है, जितनी कुछ अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं।

इस अतिरिक्त टैरिफ के बारे में पहले से ही अनुमान था, लेकिन खास बात यह रही कि ट्रंप ने चीन पर ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया, जिससे एक बार फिर उनकी “टी.ए.सी.ओ. (ट्रांप् ऑलवेज चिकन्स आउट) अर्थात् ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं, वाली छवि चरित्रार्थ होती है। चीन ने बहुत चतुराई से सेकन्डरी प्रतिबंधों से बचाव कर लिया, क्योंकि वह इस समय अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में शामिल है। यह बात तर्क से परे है, क्योंकि चीन तो रूस के युद्ध का कहीं अधिक मुखर और प्रभावी समर्थक रहा है।

‘जैसलमेर को तो मुगल भी नहीं जीत पाए थे’

जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने एन.सी.ई.आर.टी के नक्शे में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का अंग बताने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की

जैसलमेर, 06 अगस्त। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषयक पाठ्यपुस्तक में राजस्थान में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य के मानचित्र में दर्शाए जाने को लेकर जैसलमेर राजपरिवार के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने कड़ी आपत्ति जतायी है।

सिंह ने इसे ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर त्रुटि करार देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इसमें तत्काल संशोधन करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों, राजकीय अभिलेखों एवं अन्य प्रामाणिक स्रोतों में जैसलमेर में मराठा साम्राज्य के किसी प्रकार के प्रभुत्व, क़राधान, आक्रमण या हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, राजकीय पुस्तकों में भी स्पष्ट उल्लेखित है कि जैसलमेर रियासत में मराठाओं का कभी भी, कोई दखल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी जैसी शीर्ष शैक्षणिक संस्था द्वारा इस प्रकार की ऐतिहासिक त्रुटि करना, उसकी

- एन.सी.ई.आर.टी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में पेज क्रमांक 7 पर छपे इस नक्शे में जैसलमेर, बूंदी, मेवाड़ व पंजाब को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया है।
- मेवाड़ राजघराने के सदस्य व भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, बूंदी राजघराने के ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, यह हमारे पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने की कोशिश है।

विश्वसनीयता और अकादमिक गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। सिंह ने कहा कि यह विषय केवल एक मानचित्र की गलती नहीं, बल्कि जैसलमेर की ऐतिहासिक गरिमा, सांस्कृतिक अस्मिता और विद्यार्थियों को दिये जाने वाले ज्ञान की सत्यता से जुड़ा विषय है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस मानचित्र के संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की। राज परिवार के विक्रम सिंह ने बताया कि जैसलमेर के दर्ज इतिहास के अनुसार- मुगल भी जैसलमेर को नहीं

सफल रहा। जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था, लेकिन वे कभी इसे जीत नहीं पाए। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी इस राज्य ने अपने वंश गौरव एवं महत्व को यथावत रखा। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी एवं राजसमंद से भाजपा सदस्य महिमा कुमारी, बूंदी के पूर्व राजघराने के सदस्य गिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने एनसीईआरटी के शिक्षाविदों पर हमला बोलेते हुए कहा है कि यह पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने का प्रयास है। उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी के इस नक्शे में जैसलमेर, बूंदी, मेवाड़, पंजाब सहित देश के कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है। यह नक्शा एनसीईआरटी की आठवीं की सामाजिक विज्ञान की किताब इकाई-तीन में पेज नंबर 71 पर छपा है। इस नक्शे पर पूर्व राजघरानों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था, लेकिन वे कभी इसे जीत नहीं पाए। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी इस राज्य ने अपने वंश गौरव एवं महत्व को यथावत रखा। मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी एवं राजसमंद से भाजपा सदस्य महिमा कुमारी, बूंदी के पूर्व राजघराने के सदस्य गिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने एनसीईआरटी के शिक्षाविदों पर हमला बोलेते हुए कहा है कि यह पूर्वजों के बलिदान को धूमिल करने का प्रयास है। उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी के इस नक्शे में जैसलमेर, बूंदी, मेवाड़, पंजाब सहित देश के कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है। यह नक्शा एनसीईआरटी की आठवीं की सामाजिक विज्ञान की किताब इकाई-तीन में पेज नंबर 71 पर छपा है। इस नक्शे पर पूर्व राजघरानों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

एस.सी.ओ. सम्मेलन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की आवश्यकता के साथ संतुलित करना, भारत-चीन संबंधों की परिपक्वता की परीक्षा होगी। भारत के लिए यह यात्रा चीन की पाकिस्तान नीति पर असंतोष जताने के साथ-साथ व्यापार, तकनीक और बहुधुवीय वैश्विक शासन पर साझा सोच तलाशने के लिए भी होगी।

मोदी की चीन यात्रा भारत की व्यापक विदेश नीति में एक पुनर्मूल्यांकन का प्रतीक है, जो एक ध्रुवीकृत होते जा रहे विश्व में रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है। वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच यह संतुलन भारत की अगली कूटनीतिक दिशा को परिभाषित कर सकता है।

इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के साथ बातचीत में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दे शामिल रहने की संभावना है।

प्र.मंत्री ने कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय होगा। कर्तव्य भवन में पानी की ज़रूरतों के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल के उपयोग और पुनः उपयोग की व्यवस्था की गयी है। यह भवन 30 प्रतिशत कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें इमारत को ठंडा रखने और बाहरी

भारत-चीन संबंधों में स्थिरता और संवाद बहाल करने की कोशिशें की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं।

अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा तनाव कम करने के प्रयास तेज़ हुए थे और कैलाश-मासरोवर यात्रा की बहाली ने संबंधों को काफी हद तक सामान्य बनाने में मदद की थी।

2001 में स्थापित एससीओ का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को सहयोग के माध्यम से बढ़ावा देना है। इस समूह के वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं-बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।

शोर को कम करने के लिए विशेष कांच की खिड़कियां हैं। ऊर्जा-बचत करने वाली एलईडी लाइटें, ज़रूरत न होने पर लाइटें बंद करने वाले सेंसर, बिजली बचाने वाली स्मार्ट लिफ्टें और बिजली के उपयोग की परीक्षा करने की एक उन्नत प्रणाली हैं। कर्तव्य भवन-3 की छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5 लाख 34 हजार यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे।